अध्याय 14 : मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

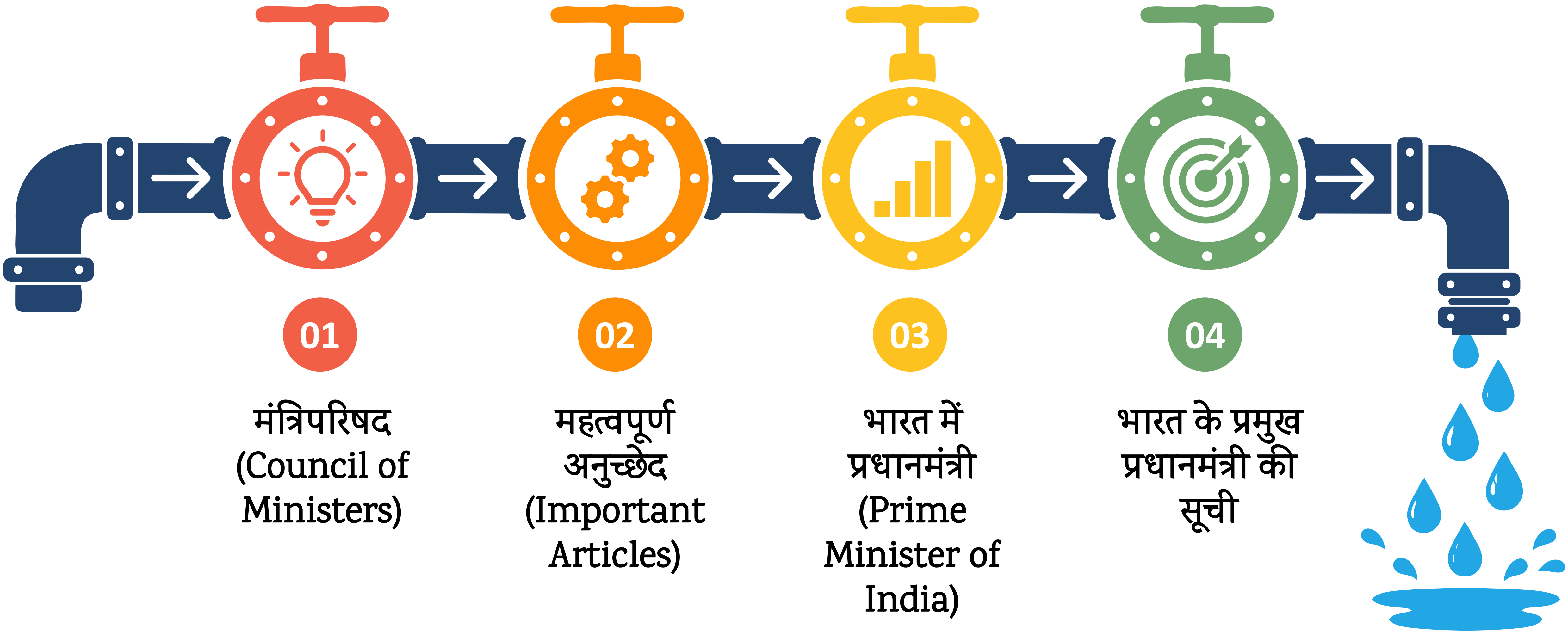

Chapter 14 : Council of Ministers

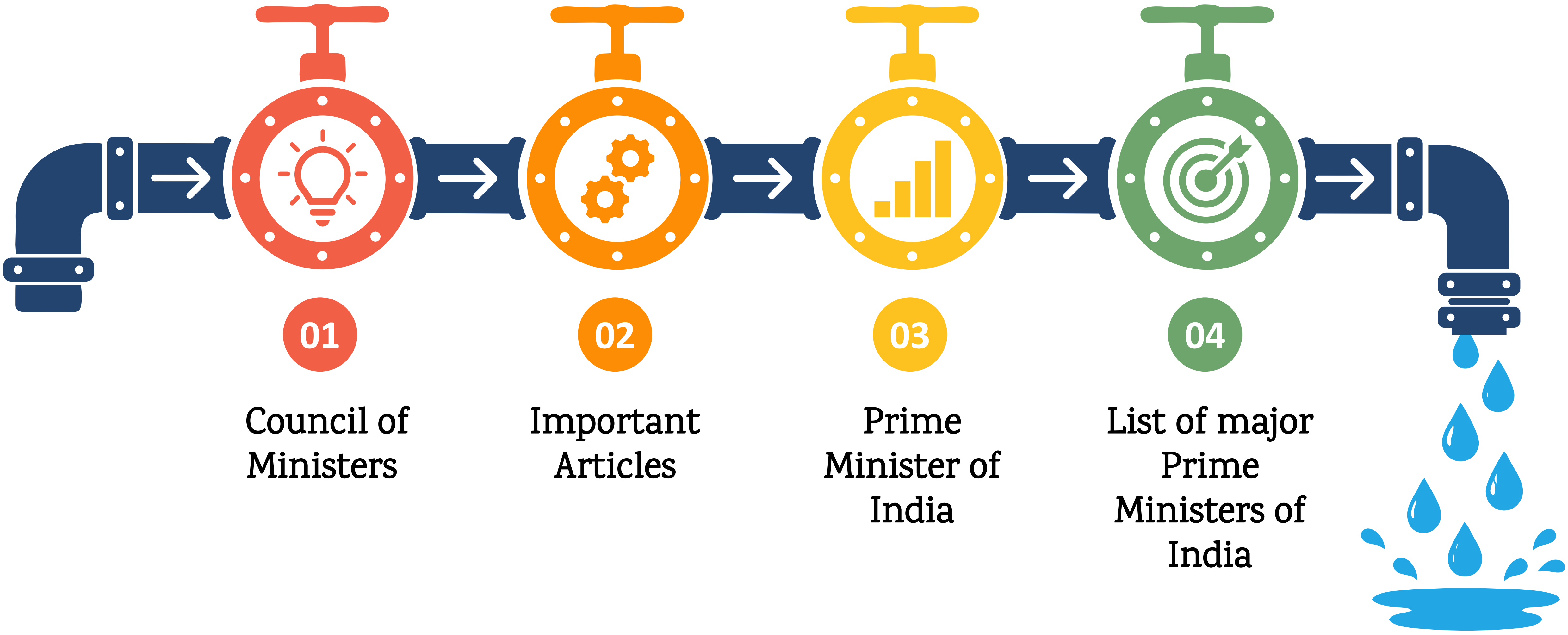

अनु. 52	भारत का राष्ट्रपति (पद का सृजन)
अनु. 53	संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित
अनु. 54–62	राष्ट्रपति का निर्वाचन, योग्यता, शपथ, महाभियोग, रिक्ति
अनु. 63–71	उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान
अनु. 72	राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति
अनु. 73	संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
अनु. 74	राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद
अनु. 75	मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध (प्रधानमंत्री सहित)
अनु. 76	भारत का महान्यायवादी (Attorney General for India)
अनु. 77	भारत सरकार के कार्य का संचालन
अनु. 78	राष्ट्रपति को सूचना देने संबंधी प्रधानमंत्री के कर्तव्य
अनु. 88	सदनों के बारे में मंत्रियों तथा महान्यायवादी के अधिकार

Art. 52	President of India (Creation of the office)
Art. 53	Executive power of the Union vested in the President
Art. 54–62	Election, qualifications, oath, impeachment, and vacancy of the President
Art. 63–71	Provisions relating to the Vice-President
Art. 72	Pardoning power of the President
Art. 73	Extent of executive power of the Union
Art. 74	Council of Ministers to aid and advise the President
Art. 75	Other provisions regarding Ministers (including the Prime Minister)
Art. 76	Attorney General for India
Art. 77	Conduct of business of the Government of India
Art. 78	Duties of the Prime Minister regarding furnishing information to the President
Art. 88	Rights of Ministers and the Attorney General as respects the Houses

1) मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

आधार	मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)	मंत्रिमंडल (Cabinet)
आकार	आमतौर पर **60 से 70 मंत्री**	आमतौर पर **15 से 20 मंत्री**
मंत्रियों की श्रेणी	तीन प्रकार के मंत्री : **कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप-मंत्री**।	केवल शीर्ष स्तर के **कैबिनेट मंत्री**
शक्तियां	इसे सभी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन केवल **सैद्धांतिक** रूप से।	यह **वास्तविक रूप** में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है।
संवैधानिक स्थिति	**अनुच्छेद 74 और 75**	मूल संविधान में 'मंत्रिमंडल' शब्द नही था। इसे **1978 में 44वें संविधान संशोधन** द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया।
उत्तरदायित्व	यह सामूहिक रूप से **लोकसभा के प्रति** उत्तरदायी होती है।	लोकसभा

1) Council of Ministers

Basis	Council of Ministers	Cabinet
Size	Usually 60 to 70 ministers	Usually 15 to 20 ministers
Category of Ministers	Three types of ministers: Cabinet Ministers, Ministers of State, and Deputy Ministers	Only top-level Cabinet Ministers
Powers	It possesses all the powers, but only in theory	It exercises the powers of the Council of Ministers in actual practice
Constitutional Status	**Articles 74 and 75**	The word 'Cabinet' was not in the original Constitution. It was added to Article 352 by the 44th Constitutional Amendment in 1978
Responsibility	It is collectively responsible to the Lok Sabha	Lok Sabha

मंत्री परिषद में मंत्रियों की श्रेणियाँ

Cabinet Minister, Minister of State, Deputy Minister

1. कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister)

स्थिति: ये सरकार के सबसे शीर्ष और शक्तिशाली मंत्री होते हैं।

प्रभार: इनके पास केंद्र सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे— गृह, रक्षा, वित्त, विदेश और रेलवे मंत्रालय। एक कैबिनेट मंत्री के पास एक से अधिक मंत्रालय भी हो सकते हैं।

अधिकार: ये 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) के मुख्य सदस्य होते हैं और सरकार की सभी महत्वपूर्ण नीतियां और फैसले इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं।

बैठक: ये मंत्रिमंडल की हर नियमित बैठक में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेते हैं।

2. राज्य मंत्री (Minister of State)

स्थिति और अधिकारों के आधार पर दो श्रेणियाँ

A. राज्य मंत्री - स्वतंत्र प्रभार (Independent Charge)

स्थिति: ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करते हैं, बल्कि अपने आवंटित मंत्रालय या विभाग के सर्वोच्च मंत्री होते हैं।

प्रभार: इन्हें आमतौर पर उन छोटे मंत्रालयों या विभागों का प्रभार दिया जाता है, जिन्हें किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं रखा जाता है।

अधिकार: अपने मंत्रालय से जुड़े सभी प्रशासनिक और नीतिगत फैसले लेने के लिए ये पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं।

बैठक: ये मंत्रिमंडल (Cabinet) के सदस्य नहीं होते। ये कैबिनेट की बैठकों में तभी शामिल होते हैं, जब इनके मंत्रालय से जुड़ा कोई विशेष मुद्दा चर्चा के लिए रखा गया हो और इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए।

B. राज्य मंत्री (अधीनस्थ / Attached)

स्थिति: ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं, बल्कि इन्हें किसी कैबिनेट मंत्री के साथ संबद्ध (attach) किया जाता है।

कार्य: कैबिनेट मंत्रियों के पास बड़े और व्यापक मंत्रालय होते हैं। उनके काम के बोझ को कम करने और मंत्रालयों के अलग-अलग विभागों को संभालने में मदद करने के लिए इन राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।

बैठक: ये मंत्रिमंडल की बैठकों में हिस्सा नहीं लेते हैं।

3. उप-मंत्री (Deputy Minister)

स्थिति: यह मंत्री परिषद में पदक्रम (Hierarchy) की सबसे निचली श्रेणी है।

कार्य: इन्हें कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) के साथ संबद्ध किया जाता है, ताकि वे उनके राजनीतिक, संसदीय और प्रशासनिक कार्यों में उनकी सहायता कर सकें।

अधिकार: इनके पास किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है।

बैठक: ये मंत्रिमंडल की बैठकों में कभी हिस्सा नहीं लेते हैं।

ध्यान दें: हाल के वर्षों में केंद्र सरकार में उप-मंत्रियों की नियुक्ति का चलन लगभग समाप्त हो गया है और अमूमन राज्य मंत्रियों तक ही परिषद सीमित रहती है।

शीर्ष स्तर कैबिनेट मंत्री → मध्य स्तर राज्य मंत्री → निम्न स्तर उप-मंत्री

Categories of Ministers in the Council of Ministers

Cabinet Minister, Minister of State, Deputy Minister

1. Cabinet Minister

Status: These are the topmost and most powerful ministers in the government.

Charge: They handle the most important ministries of the Union Government, such as Home, Defence, Finance, External Affairs, and Railways. A Cabinet Minister may also hold more than one ministry.

Authority: They are the principal members of the Cabinet, and all major government policies and decisions are taken by them.

Meetings: They compulsorily participate in every regular Cabinet meeting.

2. Minister of State

Based on status and authority, they are divided into two categories

A. Minister of State – Independent Charge

Status: They do not work under any Cabinet Minister; rather, they are the highest ministers of their allotted ministry or department.

Charge: They are usually given charge of smaller ministries or departments that are not placed under any Cabinet Minister.

Authority: They are fully independent in taking all administrative and policy decisions related to their ministry.

Meetings: They are not members of the Cabinet. They attend Cabinet meetings only when a specific issue related to their ministry is to be discussed and they are specially invited.

B. Minister of State (Attached)

Status: They do not work independently; rather, they are attached to a Cabinet Minister.

Function: Cabinet Ministers handle large and wide-ranging ministries. These Ministers of State are appointed to reduce their workload and help manage different departments of the ministry.

Meetings: They do not participate in Cabinet meetings.

3. Deputy Minister

Status: This is the lowest rank in the hierarchy of the Council of Ministers.

Function: They are attached to Cabinet Ministers or Ministers of State (Independent Charge) so that they can assist them in political, parliamentary, and administrative work.

Authority: They do not have independent charge of any department.

Meetings: They never participate in Cabinet meetings.

Note: In recent years, the practice of appointing Deputy Ministers in the Union Government has almost disappeared, and generally the Council remains limited up to Ministers of State.

Top Level – Cabinet Minister → Middle Level – Minister of State → Lower Level – Deputy Minister

विशेषता	कैबिनेट मंत्री	राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	राज्य मंत्री (अधीनस्थ)	उप-मंत्री
मंत्रालय का प्रभार	सबसे महत्वपूर्ण व बड़े मंत्रालय	छोटे मंत्रालय या विशेष विभाग	कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं	कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं
कार्यप्रणाली	पूरी तरह स्वतंत्र	अपने विभाग में स्वतंत्र	कैबिनेट मंत्री के अधीन	कैबिनेट या राज्य मंत्री के अधीन
मंत्रिमंडल (Cabinet) के सदस्य	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
कैबिनेट बैठकों में हिस्सा	हमेशा लेते हैं	केवल आमंत्रित किए जाने पर	नहीं लेते	नहीं लेते

Feature	Cabinet Minister	Minister of State (Independent Charge)	Minister of State (Subordinate)	Deputy Minister
Charge of Ministry	Most important and major ministries	Smaller ministries or specific departments	No independent charge	No independent charge
Working System	Completely independent	Independent in own department	Subordinate to a Cabinet Minister	Subordinate to a Cabinet or State Minister
Member of Cabinet	Yes	No	No	No
Participation in Cabinet Meetings	Always attend	Only when invited	Do not attend	Do not attend

मंत्रिमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

Shadow Cabinet • Kitchen Cabinet • Cabinet Committees

8.1 छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet)

- यह सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है।
- वहाँ सत्तारूढ़ दल के मंत्रिमंडल के समानांतर विपक्ष अपना मंत्रिमंडल तैयार कर लेता है।
- प्रत्येक सदस्य सरकार के किसी एक मंत्री के कार्यों पर निगरानी रखता है, समीक्षा करता है और आलोचना करता है।
- **उद्देश्य:**
  - → सरकार के कार्यों की सतत समीक्षा
  - → सत्ता में आने पर त्वरित व सुचारू संक्रमण (Smooth Transition)
  - → विपक्षी नेताओं को शासन का प्रशिक्षण
- भारत में छाया मंत्रिमंडल की परंपरा नहीं है।
- **कारण:** बहुदलीय व्यवस्था तथा प्रायः विपक्ष का विखंडित होना।

Origin → Britain

☆ स्मृति सूत्र ☆

छाया मंत्रिमंडल → ब्रिटेन

किचन कैबिनेट → अमेरिका

सूत्र: छाया-ब्रिटेन, किचन-अमेरिका

छाया में ठंडक = ब्रिटेन | रसोई में गर्मी = अमेरिका

8.2 किचन कैबिनेट (Kitchen Cabinet / रसोई मंत्रिमंडल)

- इसका विचार मूलतः अमेरिका में देखने को मिलता है।
- राष्ट्रपति अपने निजी एवं विश्वसनीय व्यक्तियों का एक अनौपचारिक सलाहकार समूह बना लेता है।
- ऐसे अनौपचारिक समूह को किचन कैबिनेट कहते हैं।
- इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन के अनौपचारिक सलाहकारों के लिए हुआ।
- भारत में भी यह अनौपचारिक रूप से रहा है।
- इसे "इनर कैबिनेट" (Inner Cabinet) भी कहा जाता है।
- इसमें सामान्यतः प्रधानमंत्री तथा 2-4 विश्वस्त सहयोगी होते हैं।
- कभी-कभी इसमें गैर-मंत्री, जैसे मित्र या परिवार के सदस्य भी प्रभावशाली हो सकते हैं।

गुण

- छोटी इकाई होने से त्वरित निर्णय
- गोपनीयता बनी रहती है

दोष

- निर्वाचित मंत्रिमंडल का महत्व घट सकता है
- बाहरी व्यक्तियों को अनुचित प्रभाव मिल सकता है

Origin → America

8.3 कैबिनेट समितियाँ (Cabinet Committees)

- ये संविधानेतर (Extra-Constitutional) निकाय हैं।
- इनका उल्लेख संविधान में नहीं, बल्कि कार्य-संचालन नियम (Rules of Business) में हैं।
- ये नियम अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत बनाए जाते हैं।
- इनका गठन प्रधानमंत्री करते हैं।
- आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या एवं संरचना बदलती रहती है।
- सामान्यतः 3 से 8 सदस्य होते हैं।
- प्रायः केवल कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं, पर कभी-कभी गैर-कैबिनेट मंत्री भी शामिल हो सकते हैं।
- **कार्य:**
  - → जटिल विषयों का परीक्षण और समाधान
  - → मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव तैयार करना
  - → सौंपे गए विषयों पर निर्णय लेना
  - → मंत्रिमंडल बाद में निर्णय की पुष्टि कर सकता है

☆ प्रमुख स्थायी कैबिनेट समितियाँ ☆

	समिति	अध्यक्ष
1.	राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) [इसे 'लघु मंत्रिमंडल"/ Super Cabinet भी कहते हैं]	प्रधानमंत्री
2.	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)	प्रधानमंत्री
3.	सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS)	प्रधानमंत्री
4.	नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (ACC)	प्रधानमंत्री
5.	संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति	सामान्यतः गृह मंत्री
6.	आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति	सामान्यतः गृह मंत्री
7.	निवेश एवं विकास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति	प्रधानमंत्री
8.	रोजगार एवं कौशल विकास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति	प्रधानमंत्री

Important Concepts Related to the Cabinet

Shadow Cabinet • Kitchen Cabinet • Cabinet Committees

8.1 Shadow Cabinet

- This concept has been borrowed from Britain.
- There, the opposition forms a parallel cabinet alongside the ruling cabinet.
- Each member keeps watch on the work of a particular minister, reviews it, and criticizes it.

★ **Purpose:**

→ Continuous review of the government's work
→ Smooth and quick transition when the opposition comes to power
→ Training opposition leaders in governance

- India does not have the tradition of a Shadow Cabinet.
- **Reason:** multi-party system and a generally fragmented opposition.

Origin → Britain

☆ Memory Trick ☆

Shadow Cabinet → Britain
Kitchen Cabinet → America

Formula: "Shadow-Britain, Kitchen-America"

Cool shadow = Britain | Hot kitchen = America

8.2 Kitchen Cabinet (Inner Cabinet)

- This concept is mainly associated with America.
- The President forms an informal group of trusted and personal advisers.
- Such an informal advisory group is called the Kitchen Cabinet.
- The term was first used for the informal advisers of U.S. President Andrew Jackson.
- In India too, such an informal arrangement has existed.
- It is also called the "Inner Cabinet".
- It usually includes the Prime Minister and 2-4 trusted associates.
- Sometimes even non-ministers, such as friends or family members, may become influential.

Merits

- Quick decision-making due to small size
- Better secrecy/confidentiality

Demerits

- Reduces the importance of the elected cabinet
- Gives undue influence to outsiders

Origin → America

8.3 Cabinet Committees

- These are Extra-Constitutional bodies.
- They are not mentioned in the Constitution; they are provided under the Rules of Business.
- These rules are made under Article 77(3).
- They are constituted by the Prime Minister.
- Their number and composition may change according to need.
- Usually they have 3 to 8 members.
- Generally, only Cabinet Ministers are members, though at times non-cabinet ministers may also be included.

★ **Functions:**

→ Examine and resolve complex issues
→ Prepare proposals for consideration by the Cabinet
→ Take decisions on matters referred to them
→ The Cabinet may later ratify/confirm such decisions

★ Major Standing Cabinet Committees ★

	Committee	Chairperson
1.	Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA) — also called the "Super Cabinet"	Prime Minister
2.	Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)	Prime Minister
3.	Cabinet Committee on Security (CCS)	Prime Minister
4.	Appointments Committee of the Cabinet (ACC)	Prime Minister
5.	Cabinet Committee on Parliamentary Affairs	Usually Home Minister
6.	Cabinet Committee on Accommodation	Usually Home Minister
7.	Cabinet Committee on Investment and Growth	Prime Minister
8.	Cabinet Committee on Employment and Skill Development	Prime Minister

2) महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Important Articles)

अनुच्छेद 74

अनुच्छेद 74(1) → राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

- मंत्रिपरिषद का प्रधान (Head) → **प्रधानमंत्री**
- राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा।
- 42वां संविधान संशोधन अधिनियम (1976) : राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना पूरी तरह से बाध्यकारी है।
- 44वां संविधान संशोधन अधिनियम (1978) : मंत्रिपरिषद की सलाह को **एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा** सकता है।

अनुच्छेद 74(2) → मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इस **बात की जांच किसी भी न्यायालय (Court) में नहीं** की जा सकती है।

'विधिक उत्तरदायित्व नहीं है' - भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी सार्वजनिक या शासकीय कार्य (Public Act) के लिए किसी मंत्री को कानूनी रूप से न्यायालय में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह अवधारणा ब्रिटेन में लागू है

2) Important Articles

Article 74

Article 74(1) → Council of Ministers to aid and advise the President

- Head of the Council of Ministers → Prime Minister
- The President shall exercise his functions only in accordance with the advice of the Council of Ministers.
- 42nd Constitutional Amendment Act (1976): It is fully binding on the President to accept the advice of the Council of Ministers
- 44th Constitutional Amendment Act (1978): The President may return the advice once for reconsideration

Article 74(2) → The advice given by ministers to the President cannot be inquired into in any court

'No legal responsibility' - No minister can be held legally accountable in court for any public or official act (Public Act) performed by the President of India. This concept applies in Britain

अनुच्छेद 75

- अनुच्छेद 75(1) → **राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रियों** की नियुक्ति (प्रधानमंत्री की सलाह पर)
- अनुच्छेद 75(1A)→ 91 संशोधन अधिनियम, 2003
  - मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या **लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं** हो सकती → **अधिकतम 81 मंत्री (प्रधानमंत्री सहित)**
- अनुच्छेद 75(1B)→ 91 संशोधन अधिनियम, 2003 → **दल-बदल** के कारण मंत्री पद के लिए अयोग्यता
- अनुच्छेद 75(2) → सभी मंत्री **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** अपना पद धारण करेंगे → व्यक्तिगत उत्तरदायित्व
- अनुच्छेद 75(3) → मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी
  - **सामूहिक उत्तरदायित्व (ब्रिटेन) → अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है।**
- अनुच्छेद 75(4) → **राष्ट्रपति सभी मंत्रियों** को पद और गोपनीयता की **शपथ** दिलाते हैं
- अनुच्छेद 75(5) → यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे **6 महीने के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता हासिल** करना अनिवार्य है।
- अनुच्छेद 75(6) → मंत्रियों के **वेतन और भत्ते** वे होंगे, जो संसद समय-समय पर कानून बनाकर निर्धारित करेगी → "मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952" + दूसरी अनुसूची

Article 75

- Article 75(1) → Appointment of the Prime Minister and ministers by the President (on the advice of the Prime Minister
- Article 75(1A) → 91st Amendment Act, 2003
  - The total number of ministers in the Council of Ministers, including the Prime Minister, cannot exceed 15% of the total membership of the Lok Sabha → maximum 81 ministers (including the Prime Minister)
- Article 75(1B) → 91st Amendment Act, 2003 → Disqualification for the office of minister due to defection
- Article 75(2) → All ministers shall hold office during the pleasure of the President → individual responsibility
- Article 75(3) → The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha
  - **Collective responsibility (Britain) → A no-confidence motion can be brought only in the Lok Sabha**
- Article 75(4) → The President administers the oaths of office and secrecy to all ministers
- Article 75(5) → If a person is not a member of Parliament when becoming a minister, it is mandatory for him to acquire membership of either House within 6 months
- Article 75(6) → The salaries and allowances of ministers shall be as determined by Parliament from time to time by law → "The Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952" + Second Schedule

अनुच्छेद 77

- 77(1) → भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से।
- 77(2) → राष्ट्रपति के नाम से जारी किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को उस तरीके से प्रमाणित (Authenticate) किया जाएगा, जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट हो।
- **77(3) → राष्ट्रपति भारत सरकार के "कार्य-संचालन नियम" नियम बनाएगा।**
  - Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961
  - Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961:

अनुच्छेद 78

- प्रधानमंत्री → केंद्र सरकार)के प्रशासन और नए कानूनों के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को दे।
- प्रधानमंत्री → राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना
- यदि राष्ट्रपति चाहें, तो वे प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकते हैं कि वह ऐसे किसी भी मामले को पूरी मंत्रिपरिषद (Cabinet) के समक्ष विचार के लिए रखे, जिस पर किसी मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले लिया है, लेकिन जिस पर पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है।

Article 77

- Article 77(1) → All executive action of the Government of India shall be taken in the name of the President
- Article 77(2) → Orders and other instruments issued in the name of the President shall be authenticated in the manner specified in the rules made by the President
- **Article 77(3) → The President shall make the "Rules of Business" of the Government of India**
  - Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961
  - Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961:

Article 78

- Prime Minister → shall communicate to the President all decisions relating to the administration of the affairs of the Union (Central Government) and proposals for new legislation
- Prime Minister → to furnish information requested by the President
- If the President so desires, he may direct the Prime Minister to place before the full Council of Ministers (Cabinet) for consideration any matter on which a minister has taken a decision individually but which has not been considered by the full Council of Ministers.

अनुच्छेद 88

- संसद के सदनों के संबंध में मंत्रियों और भारत के महान्यायवादी के अधिकारों
- **प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी → भाग लेने और बोलने का अधिकार**
  - संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा)
  - संयुक्त बैठक (Joint Sitting)
  - संसदीय समितियां
- **मतदान**
  - मंत्री → मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह चुना हुआ सदस्य होता है
  - **महान्यायवादी** → मतदान करने का **कोई अधिकार नहीं**

यू.एन.आर. राव (1971)	**लोकसभा भंग होने पर भी मंत्रिपरिषद बनी रहती है।**
शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)	**राष्ट्रपति एवं राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख मात्र हैं; वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है।**
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)	**सरकार का बहुमत राजभवन/राष्ट्रपति भवन में नहीं, सदन के पटल (Floor of the House) पर सिद्ध होगा।**
राम जवाया कपूर (1955)	**भारत में संसदीय व्यवस्था है; कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रयुक्त होती है।**

Article 88

- Rights of Ministers and the Attorney General of India in relation to the Houses of Parliament
- **Every minister and the Attorney General of India → right to take part and speak**
  - In either House of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha)
  - Joint sitting
  - Parliamentary committees
- **Voting**
  - Minister → can vote only in the House of which he is an elected member
  - **Attorney General** → has no right to vote

U.N.R. Rao (1971)	The Council of Ministers continues to exist even if the Lok Sabha is dissolved.
Shamsher Singh vs. State of Punjab (1974)	The President and the Governor are merely constitutional heads; the real power lies with the Council of Ministers.
S.R. Bommai vs. Union of India (1994)	The government's majority must be proved not in the Raj Bhavan/Rashtrapati Bhavan, but on the Floor of the House.
Ram Jawaya Kapoor (1955)	India has a parliamentary system; executive power is exercised through the Council of Ministers.

- 'विधिक उत्तरदायित्व नहीं है' - भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी सार्वजनिक या शासकीय कार्य (Public Act) के लिए किसी मंत्री को कानूनी रूप से न्यायालय में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह अवधारणा ब्रिटेन में लागू है
- **91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 164(1A)**
  - **दिनेश गोस्वामी समिति एवं विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट की** सिफारिशों पर आधारित
  - दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) में संशोधन — **"विभाजन" (Split) के आधार पर मिलने वाली छूट समाप्त कर दी;** अब केवल **विलय (दो-तिहाई सदस्य)** ही मान्य है।
  - **अनुच्छेद 164(1A) —**
    - ✓ किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी
    - ✓ किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
  - **अनुच्छेद 75(1A) —** प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।

- 'No legal responsibility' - No minister can be held legally accountable in court for any public or official act performed by the President of India. This concept applies in Britain
- Article 164(1A), added under the 91st Constitutional Amendment Act, 2003)
  - **Based on the recommendations of the Dinesh Goswami Committee and the 170th Report of the Law Commission**
  - Amendment to the Anti-Defection Law (10th Schedule) — abolished the exemption granted on the ground of "split"; now only merger (two-thirds members) is valid
  - Article 164(1A) -
    - ✓ The total number of ministers in the Council of Ministers of any state, including the Chief Minister, shall not exceed 15% of the total membership of that state's Legislative Assembly
    - ✓ The number of ministers, including the Chief Minister, in any state shall not be less than 12
  - Article 75(1A) - The total number of ministers in the Union Council of Ministers, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total membership of the Lok Sabha

91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003
(91st Constitutional Amendment Act, 2003)

सत्यमेव जयते

मुख्य उद्देश्य: शासन प्रणाली में सुधार, अनावश्यक रूप से बड़े मंत्रिमंडलों (Jumbo Cabinets) पर रोक, तथा दलबदल (Defection) की राजनीति को अधिक सख्त बनाना।

संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 361B और 10वीं अनुसूची में महत्वपूर्ण बदलाव

1 1. मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना

- **अनुच्छेद 75(1A):** प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के **15%** से अधिक नहीं होगी।
- **अनुच्छेद 164(1A):** मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के **15%** से अधिक नहीं होगी।
- **अपवाद:** किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या **12** से कम नहीं होगी।

2 2. दलबदलुओं को मंत्री बनने से रोकना

- **अनुच्छेद 75(1B) और 164(1B):** 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित सदस्य अपनी अयोग्यता की अवधि तक मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा।
- इससे वह खामी दूर हुई, जिसमें दलबदल करने वाले सदस्य इस्तीफा देकर तुरंत मंत्री बन जाते थे।

3 3. लाभ के राजनीतिक पद पर रोक

- **अनुच्छेद 361B:** दलबदल के आधार पर अयोग्य चोषित सदस्य अपनी अयोग्यता की अवधि तक कोई भी **'लाभकारी राजनीतिक पद'** (Remunerative Political Post) धारण नहीं कर सकता।
- **अर्थ:** ऐसा पद, जिसके लिए वेतन या पारिश्रमिक सरकार के सार्वजनिक राजस्व से दिया जाता हो।
- **उदाहरण:** किसी बोर्ड या निगम का अध्यक्ष।

4 4. 10वीं अनुसूची में बदलाव

पहले का नियम	नया नियम
पैराग्राफ 3 के अनुसार, यदि किसी दल के **1/3** सदस्य अलग होकर नया गुट बनाते थे, तो उन्हें अयोग्य नहीं माना जाता था।	91वें संशोधन ने पैराग्राफ 3 समाप्त कर दिया। अब 1/3 विभाजन मान्य नहीं है। अब दलबदल से बचने के लिए कम से कम **2/3** सदस्यों का किसी अन्य दल में **'विलय'** (Merger) आवश्यक है।
1/3 Split — समाप्त	**2/3 Merger — मान्य**

निष्कर्ष

91वें संविधान संशोधन ने भारतीय राजनीति में मंत्री पद या लाभकारी पद का लालच देकर पार्टियां तोड़ने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाई। इससे सार्वजनिक धन की बचत हुई और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिला।

91st Constitutional Amendment Act, 2003

91st Constitutional Amendment Act, 2003

Satyameva Jayate

Main Objective: To improve the system of governance, prevent unnecessarily large 'Jumbo Cabinets', and make the politics of defection more stringent.

Important changes in Articles 75, 164, 361B and the 10th Schedule of the Constitution

1. Limiting the Size of the Council of Ministers

- **Article 75(1A):** The total number of ministers in the Union Council of Ministers, including the Prime Minister, shall not exceed **15%** of the total strength of the Lok Sabha.
- **Article 164(1A):** The total number of ministers in a State Council of Ministers, including the Chief Minister, shall not exceed **15%** of the total strength of the State Legislative Assembly.
- **Exception:** In any state, the number of ministers shall not be less than **12**.

2. Preventing Defectors from Becoming Ministers

- **Articles 75(1B) and 164(1B):** A member of Parliament or a State Legislature disqualified under the 10th Schedule shall also be disqualified from becoming a minister during the period of disqualification.
- This removed the earlier loophole under which defectors could resign and immediately take oath as ministers.

3. Bar on Remunerative Political Posts

- **Article 361B:** A member disqualified on the ground of defection cannot hold any 'Remunerative Political Post" during the period of disqualification.
- **Meaning:** A post for which salary, remuneration, or other financial benefit is paid from the public revenue of the Central or State Government.
- **Example:** Chairperson of a board or corporation.

4. Changes in the 10th Schedule

Old Rule

Earlier, under Paragraph 3, if one-third **(1/3)** members of a political party split away and formed a separate group, they were not disqualified.

1/3 Split — Removed

New Rule

The 91st Amendment omitted Paragraph 3. Now, a split by one-third members is not valid. To avoid disqualification, at least two-thirds **(2/3)** members must merge with another party.

2/3 Merger — Valid

Conclusion

The 91st Constitutional Amendment curbed the practice of breaking parties by offering ministerial posts or other political offices to legislators and MPs. It helped save public money and promoted political stability.

3) भारत में प्रधानमंत्री (Prime Minister of India)

❑ परिचय :-

- भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है।
- **राष्ट्रपति** → 'नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख' (Nominal Executive/Head of State)
- वास्तविक शक्तियां (Head of Government) → **प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद**

❑ नियुक्ति :-

- अनुच्छेद 75 → प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे
- **प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव नहीं होता** → लोकसभा चुनाव में जिस दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं।
- बहुमत का अंक → 543 ÷ 2 = **272**
- **त्रिशंकु लोकसभा** की स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर **सबसे बड़े दल** के नेता को सरकार बनाने का न्यौता देते हैं।
- राष्ट्रपति के पास कोई **एक निश्चित नियम नहीं** होता है।

3) Prime Minister of India

❑ Introduction :-

- India has adopted a parliamentary system of government
- **President** → 'Nominal Executive/Head of State'
- Head of Government → **Prime Minister and his Council of Ministers)**

❑ Appointment :-

- Article 75 → The Prime Minister shall be appointed by the President, and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister
- **The Prime Minister is not directly elected** → the President appoints as Prime Minister the leader of the party or alliance that wins a full majority in the Lok Sabha elections.
- Majority mark → 543 ÷ 2 = 272
- In the case of a hung Lok Sabha, the President uses his own discretion to invite the leader of the largest party to form the government.
- The President does not have any single fixed rule for this

❑ योग्यता :-

- भारत का नागरिक
- संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य होना चाहिए।
- आयु सीमा :
  - ✓ 25 वर्ष (यदि वह लोकसभा का सदस्य है)
  - ✓ 30 वर्ष (यदि वह राज्यसभा का सदस्य है)
- किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए
- अनुच्छेद 75(5) → कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे भी 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी।
- उदाहरण : 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव

❑ शपथ → अनुच्छेद 75(4) :-

- भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति
- दो शपथ—
  - ✓ पद की शपथ (Oath of Office)
  - ✓ गोपनीयता की शपथ (Oath of Secrecy)
- शपथ का प्रारूप → तीसरी अनुसूची
- कार्यकाल → कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं
  - ✓ 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत'
- वेतन (Salary) → संसद द्वारा निर्धारित
- प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र होते ही सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है
- लोकसभा में विश्वास खो देने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है

❑ Qualifications :-

- Must be a citizen of India
- Must be a member of either House of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha)
- Age limit :
  - ✓ 25 years (if he is a member of the Lok Sabha)
  - ✓ 30 years (if he is a member of the Rajya Sabha)
- Must not hold any office of profit
- Article 75(5) → A person who is not a member of Parliament can also be appointed Prime Minister for 6 months. But within 6 months he must take membership of one House
- Example : P.V. Narasimha Rao in 1991

❑ Oath → Article 75(4) :-

- Administered by the President of India or a person appointed by the President
- Two oaths -
  - ✓ Oath of Office
  - ✓ Oath of Secrecy
- Format of the oath → Third Schedule
- Tenure → no fixed term prescribed
  - ✓ 'During the pleasure of the President'
- Salary → determined by Parliament
- As soon as the Prime Minister dies or resigns, the entire Council of Ministers is automatically dissolved
- On losing the confidence of the Lok Sabha, the Council of Ministers is dissolved and the Prime Minister has to resign

❑ प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य :-

- मंत्रिपरिषद का प्रमुख
- मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश
- विभागों का आवंटन
- किसी मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी सलाह देते हैं
- प्रधानमंत्री सदन का नेता (Leader of the House) होता है — उस सदन का, जिसका वह सदस्य है।

निकाय	प्रधानमंत्री की भूमिका
नीति आयोग (NITI Aayog)	पदेन अध्यक्ष (2015 से; योजना आयोग का स्थान लिया)
अंतर-राज्य परिषद (अनु. 263)	पदेन अध्यक्ष
राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)	पदेन अध्यक्ष
राष्ट्रीय एकता परिषद (NIC)	पदेन अध्यक्ष
राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद	पदेन अध्यक्ष
परमाणु कमान प्राधिकरण (NCA)	परमाणु हथियारों के प्रयोग का अंतिम अधिकार
सामान्यतः प्रधानमंत्री के अधीन विभाग	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग; तथा ऐसे समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को न सौंपे गए हों

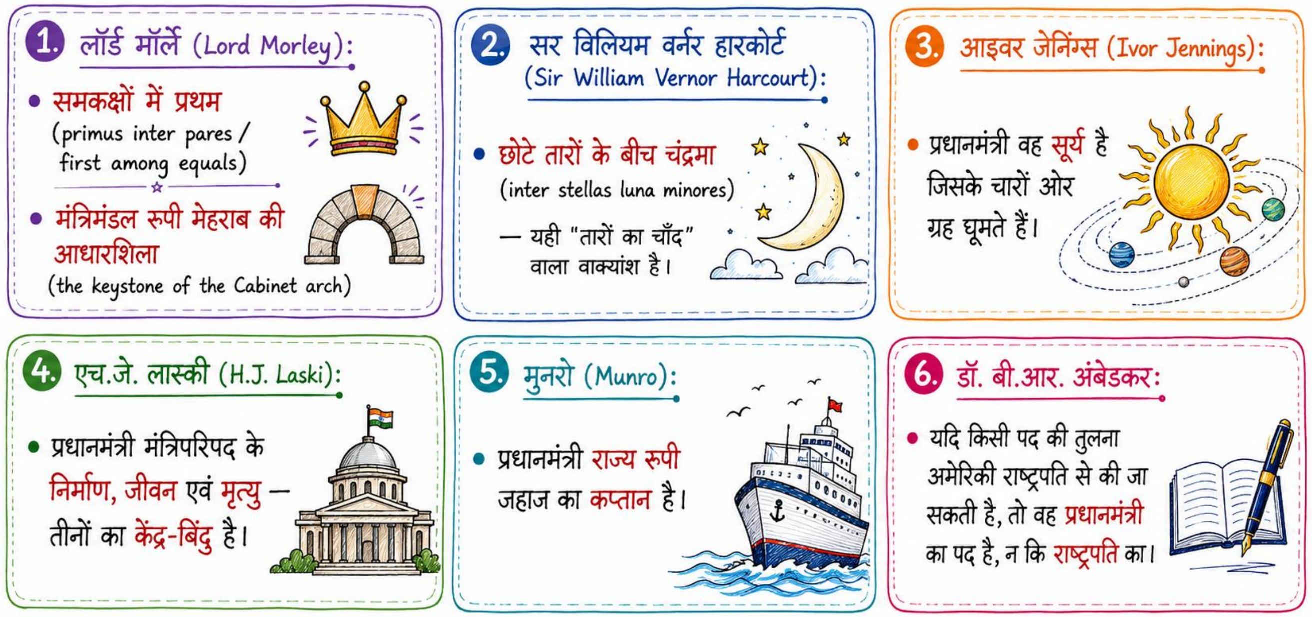

❑ Powers and Functions of the Prime Minister :-

- Head of the Council of Ministers
- Recommends the appointment of ministers
- Allocation of departments (portfolios)
- Can ask a minister to resign, or advise the President to dismiss him.
- The Prime Minister advises the President on appointments
- The Prime Minister is the Leader of the House — of the House of which he is a member.

Body	Role of the Prime Minister
NITI Aayog	Ex-officio Chairman (since 2015; replaced the Planning Commission)
Inter-State Council (Art. 263)	Ex-officio Chairman
National Development Council (NDC)	Ex-officio Chairman
National Integration Council (NIC)	Ex-officio Chairman
National Water Resources Council	Ex-officio Chairman
Nuclear Command Authority (NCA)	Final authority for use of nuclear weapons
Depa[illegible] the P[illegible]	Ministry of Personnel, Public Grievances and [illegible] s

उपप्रधानमंत्री — एक संविधानेतर पद

- संविधान में **उपप्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं** है
- उपप्रधानमंत्री की शक्तियाँ एक कैबिनेट मंत्री से अधिक नहीं होतीं और उसकी शपथ भी मंत्री के रूप में ही दिलाई जाती है।
- 1990 में चौधरी देवीलाल द्वारा "उपप्रधानमंत्री" के रूप में ली गई शपथ को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी; न्यायालय ने शपथ को वैध ठहराते हुए कहा कि "उपप्रधानमंत्री" शब्द केवल वर्णनात्मक (descriptive) है और वास्तव में वह मंत्री की ही शपथ है।
- सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री थे।
- लाल कृष्ण आडवाणी अब तक के अंतिम उपप्रधानमंत्री हैं (2002–2004)।
- कुल 7 व्यक्ति इस पद पर रहे हैं।

क्र	उपप्रधानमंत्री	कार्यकाल	प्रधानमंत्री
1	सरदार वल्लभभाई पटेल	1947 – 1950	जवाहरलाल नेहरू
2	मोरारजी देसाई	1967 – 1969	इंदिरा गांधी
3	चौधरी चरण सिंह	1979	मोरारजी देसाई
4	बाबू जगजीवन राम	1979	मोरारजी देसाई
5	वाई.बी. चव्हाण	1979 – 1980	चौधरी चरण सिंह
6	चौधरी देवीलाल	1989–1990 तथा 1990–1991	वी.पी. सिंह तथा चंद्रशेखर
7	लाल कृष्ण आडवाणी	2002 – 2004	अटल बिहारी वाजपेयी

Deputy Prime Minister — an extra-constitutional post

- There is no mention of the Deputy Prime Minister in the Constitution)
- The powers of the Deputy Prime Minister are no greater than those of a Cabinet minister, and he too is administered the oath as a minister.
- The oath taken by Chaudhary Devi Lal as "Deputy Prime Minister" in 1990 was challenged in the Supreme Court; the Court upheld the oath as valid, holding that the term "Deputy Prime Minister" is merely descriptive and it is, in fact, the oath of a minister.
- Sardar Vallabhbhai Patel was India's first Deputy Prime Minister.
- Lal Krishna Advani is the most recent Deputy Prime Minister so far (2002–2004).
- A total of 7 people have held this post.

S. No.	Deputy Prime Minister	Tenure	Prime Minister
1	Sardar Vallabhbhai Patel	1947 – 1950	Jawaharlal Nehru
2	Morarji Desai	1967 – 1969	Indira Gandhi
3	Chaudhary Charan Singh	1979	Morarji Desai
4	Babu Jagjivan Ram	1979	Morarji Desai
5	Y. B. Chavan	1979 – 1980	Chaudhary Charan Singh
6	Chaudhary Devi Lal	1989–1990 and 1990–1991	V. P. Singh and Chandra Shekhar
7	Lal Krishna Advani	2002 – 2004	Atal Bihari Vajpayee

1. नियुक्ति और बहुमत के नियम

लोकसभा (LS) में बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है।

सामान्य नियम: बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री (PM) नियुक्त किया जाता है।

अपवाद (जब बहुमत न हो): यदि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है।

बहुमत सिद्ध करना (Floor Test): ऐसे मामलों में, नियुक्त प्रधानमंत्री को 30 दिनों के भीतर सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है।

2. शपथ और संसदीय सदस्यता

शपथ: प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।

सदस्यता की आवश्यकता: प्रधानमंत्री को संसद के किसी एक सदन (लोकसभा - LS, या राज्यसभा - RS) का सदस्य होना अनिवार्य है।

गैर-सदस्यों के लिए समय सीमा: यदि नियुक्त प्रधानमंत्री नियुसति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो उन्हें 6 माह के भीतर सदस्यता प्राप्त करनी होगी।

3. राज्यसभा (राज्यों की परिषद) के सदस्य रहे प्रधानमंत्री

1.
   इंदिरा गांधी
   (1966)
2.
   एच. डी. देवगौड़ा
   (हरदननहली डोड्डेगौड़ा देवगौड़ा)
   (1996)
3.
   आई. के. गुजराल
   (इन्द्र कुमार गुजराल)
   (1997)
4.
   मनमोहन सिंह
   (2004)

1. Rules of Appointment and Majority

A majority in the Lok Sabha (LS) requires 272 seats.

General Rule: The leader of the majority party is appointed as the Prime Minister (PM).

Exception (When There Is No Majority): If no party gets a clear majority, the leader of the largest party is appointed as the Prime Minister.

Proving Majority (Floor Test): In such cases, the appointed Prime Minister must prove his or her majority on the floor of the House within 30 days.

2. Oath and Parliamentary Membership

Oath: The Prime Minister is administered the oath of office by the President.

Membership Requirement: The Prime Minister must be a member of either House of Parliament — Lok Sabha (LS) or Rajya Sabha (RS).

Time Limit for Non-Members: If the appointed Prime Minister is not a member of either House at the time of appointment, he or she must obtain membership within 6 months.

3. Prime Ministers Who Were Members of the Rajya Sabha (Council of States)

1. **Indira Gandhi** (1966)
2. **H. D. Deve Gowda** (Haradanahalli Doddiegowda Deve Gowda) (1996)
3. **I. K. Gujral** (Inder Kumar Gujral) (1997)
4. **Manmohan Singh** (2004)

4) भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री की सूची

4) List of major Prime Ministers of India

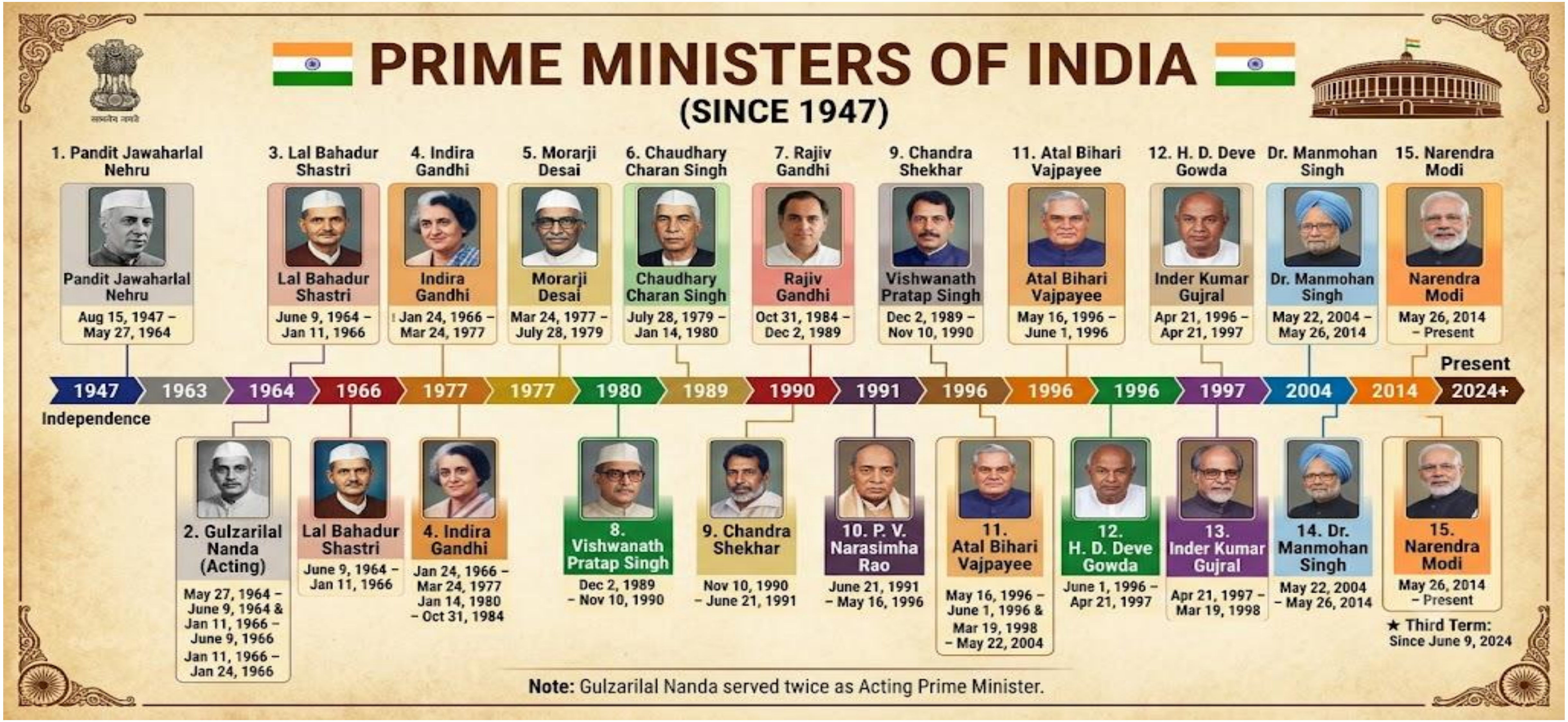

रिकॉर्ड / तथ्य : प्रधानमंत्री

	रिकॉर्ड / तथ्य	प्रधानमंत्री
1.	सबसे लंबे समय तक सेवारत PM	जवाहरलाल नेहरू (16 वर्ष 286 दिन)
2.	सबसे कम समय तक सेवारत PM (नियमित)	अटल बिहारी वाजपेयी (1996, 13 दिन)
3.	सबसे युवा PM (शपथ के समय)	राजीव गांधी (40 वर्ष)
4.	सबसे वृद्ध PM (शपथ के समय)	मोरारजी देसाई (81 वर्ष)
5.	एकमात्र महिला PM	इंदिरा गांधी
6.	प्रथम गैर-कांग्रेसी PM	मोरारजी देसाई
7.	एकमात्र PM जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया	चरण सिंह
8.	दो बार कार्यवाहक PM बनने वाले एकमात्र व्यक्ति	गुलज़ारीलाल नंदा
9.	दक्षिण India से प्रथम PM	पी.वी. नरसिम्हा राव
10.	प्रथम सिख PM	मनमोहन सिंह
11.	लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले (नेहरू के पश्चात्)	नरेंद्र मोदी (2024)
12.	पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम गैर-कांग्रेसी PM	अटल बिहारी वाजपेयी (1998–2004)

सत्यमेव जयते

Records / Facts : Prime Ministers

	Record / Fact	Prime Minister
1.	Longest-serving PM	Jawaharlal Nehru (16 years 286 days)
2.	Shortest-serving PM (regular)	Atal Bihari Vajpayee (1996, 13 days)
3.	Youngest PM (at the time of oath)	Rajiv Gandhi (40 years)
4.	Oldest PM (at the time of oath)	Morarji Desai (81 years)
5.	Only woman PM	Indira Gandhi
6.	First non-Congress PM	Morarji Desai
7.	Only PM who never faced Parliament	Charan Singh
8.	Only person to become Acting PM twice	Gulzarilal Nanda
9.	First PM from South India	P. V. Narasimha Rao
10.	First Sikh PM	Manmohan Singh
11.	Took oath for a third consecutive term (after Nehru)	Narendra Modi (2024)
12.	First non-Congress PM to complete a full term	Atal Bihari Vajpayee (1998–2004)

Satyameva Jayate

राज्यसभा से आने वाले प्रधानमंत्री (कुल 4)

क्रम	प्रधानमंत्री	वर्ष	टिप्पणी
1	इंदिरा गांधी	1966	प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से बने; बाद में 1967 के आम चुनाव में लोकसभा (रायबरेली) से निर्वाचित हुईं
2	एच.डी. देवगौड़ा	1996	नियुक्ति के समय कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य थे; बाद में राज्यसभा सदस्य बने
3	आई.के. गुजराल (इन्द्र कुमार गुजराल)	1997	राज्यसभा सदस्य
4	डॉ. मनमोहन सिंह	2004	सम्पूर्ण कार्यकाल (2004–2014) राज्यसभा सदस्य रहते हुए;

ऐसे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहे

प्रधानमंत्री	किस राज्य के मुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री कार्यकाल
मोरारजी देसाई	बंबई राज्य (Bombay State)	1952 – 1956
चौधरी चरण सिंह	उत्तर प्रदेश	1967–68 तथा 1970
वी.पी. सिंह (विश्वनाथ प्रताप सिंह)	उत्तर प्रदेश	1980 – 1982
पी.वी. नरसिंह राव	आंध्र प्रदेश	1971 – 1973
एच.डी. देवगौड़ा	कर्नाटक	1994 – 1996
नरेंद्र मोदी	गुजरात	2001 – 2014

Prime Ministers who came from the Rajya Sabha (total 4)

S.No.	Prime Minister	Year	Remarks
1	Indira Gandhi	1966	First Prime Minister to become PM from the Rajya Sabha; later elected to the Lok Sabha (Rae Bareli) in the 1967 general election
2	H. D. Deve Gowda	1996	Was a member of the Karnataka Legislative Council at the time of appointment; later became a Rajya Sabha member
3	I. K. Gujral (Inder Kumar Gujral)	1997	Rajya Sabha member
4	Dr. Manmohan Singh	2004	Remained a Rajya Sabha member throughout his entire tenure (200–2014)

Prime Ministers who also served as Chief Ministers

Prime Minister	Chief Minister of Which State	Chief Minister Tenure
Morarji Desai	Bombay State	1952 – 1956
Chaudhary Charan Singh	Uttar Pradesh	1967–68 and 1970
V. P. Singh (Vishwanath Pratap Singh)	Uttar Pradesh	1980 – 1982
P. V. Narasimha Rao	Andhra Pradesh	1971 – 1973
H. D. Deve Gowda	Karnataka	1994 – 1996
Narendra Modi	Gujarat	2001 – 2014